खंड: 3, अंक: 11 नवंबर 2023 DELHIN/2021/84711

संश्लेषण

डी सी आर सी मासिक पत्रिका

भारतीय चुनावी लोकतंत्र: परिवर्तनीयता एवं गत्यात्मकता

डी सी आर सी

विकासशील राज्य शोध केंद्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

संश्लेषण

आरंभिक वर्ष एवं माह	–	सितंबर 2021
आवृत्ति	–	मासिक
प्रारूप	–	मुद्रित
मुख्य विषय	–	सामाजिक विज्ञान
भाषा	–	हिंदी

उद्देश्य

संश्लेषण हिंदी मासिक पत्रिका हिंदी भाषा की एक विषयगत पत्रिका है। जो समसामयिक विषयों पर छात्रों और विद्वानों, अध्येताओं और संकाय सदस्यों, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं से आलेख आमंत्रित करती है। पत्रिका के कुछ प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं: –

1. हिन्दी के नव लेखकों को एक मंच प्रदान करना इस पत्रिका का प्रधान उद्देश्य है।
2. शैक्षणिक समुदाय के विभिन्न वर्गों से विचारों की बहुलता और विविधता को व्यक्त करना।
3. राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्रों से संबंधित समसामयिक विषयों को व्यक्त करना।
4. अकादमिक लेखन के परिप्रेक्ष्य से सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में परिवर्तन व चुनौतियों का समाधान करना।
5. नीति निर्माण और शासन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर विचार करना।
6. युवा स्वरों को एक व्यापक शैक्षणिक मंच प्रदान करना जो विकास व शासन के नए वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत करता है।

क्षेत्र

संश्लेषण एक मासिक पत्रिका है जो बहुविषयक में ब्लाइंड पीयर–समीक्षित शोध प्रकाशित करती है, यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है, हमारा उद्देश्य विश्व भर में मान्यता व शीघ्रता से प्रकाशन करना है। आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्र में में हो रहे

परिवर्तन के बारे में बताता है। हमारी पत्रिका हमारे पाठकों के माध्यम से प्रकाशन पहुंचाने और प्रसंस्करण के लिए एक सुविधाजनक, विश्वसनीय व लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने में सहायता करती है।

उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्र प्रकाशित करना तथा मौलिक नवोन्चेषी एवं नवीन शोध लेख प्रकाशित करना, इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य रहा है। यह अकादमिक विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के विधार्थीयों, शोधार्थीयों व शिक्षार्थियों के वर्तमान व महत्वपूर्ण शोध के साथ–साथ प्रकाशन गतिविधियों को प्रकाशित करने की सुविधा प्रदान करती है। यह पत्रिका सभी क्षेत्रों पर शोध आलेख स्वीकार करती है।

समीक्षित व रेफरीड शोध पत्रिकाएँ व्यापक क्षेत्रों में ज्ञान और समझ की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन पत्रिकाओं को उच्चतम गुणवत्ता वाला माना जाता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रकाशित शोध को उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन की एक कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे हिंदी में शोध समीक्षा व मुल्यांकन के नाम से जाना जाता है।

मूल्यांकन का उद्देश्य शोध कार्य की गुणवत्ता व वैधता का आकलन करना तथा सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना है। मुल्यांकन अनुसंधान के उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों व शिक्षार्थियों द्वारा किया जा सकता है। शोध समीक्षा और मूल्यांकन दोनों ही शोध प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण हैं व शोध की गुणवत्ता तथा वैधता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, उच्च गुणवत्ता वाली समीक्षा व रेफरीड शोध पत्रिकाओं में हितों के टकराव से निपटने के लिए एक स्पष्ट तथा पारदर्शी प्रक्रिया भी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से किया जाता है और किसी भी संभावित पूर्वाग्रह की पहचान की जाती है और उसे ध्यान में रखा जाता है। उच्च–गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशित करके, ये पत्रिकाएँ शोधकर्ताओं, अभ्यासकर्ताओं तथा नीति निर्माताओं के लिए एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करती हैं।

संपादक

प्रोफेसर सुनील कुमार

निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: director@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://cgs.du.ac.in/directorMessage.html

संपादक मंडल

डॉ रमेश कुमार भारद्वाज

सहायक आचार्य, सरकारी पी.जी कॉलेज, जीवाजी विश्वविद्यालय, श्योपुर पाली रोड, मध्य प्रदेश, पिन कोड-476337
संयुक्त निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: rkbhardwaj1@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.mphighereducation.nic.in

डॉ महेश कौशिक

सहायक आचार्य, श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: mkaushik@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.aurobindo.du.ac.in

डॉ संध्या वर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: sverma@shyamlale.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://shyamlale.du.ac.in/wp-content/uploads/2021/11/sandhya-Verma-Political-Science.pdf

डॉ सुरेन्द्र सिंह

सहायक आचार्य, आत्मा राम सनातन धर्मा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, धौला कुआं, नई दिल्ली-110021
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: ssingh@arsd.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.arsdcollege.ac.in/faculty-members/

विकासशील राज्य शोध केंद्र (डीसीआरसी), एआरसी बिल्डिंग, गुरू तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-**110007** की ओर से सुनील कुमार द्वारा प्रकाषित एवं सी के प्रिटिंग प्रेस, 5-ए/177-178, गली न० 7, डब्ल्यू, करोल बाग नई दिल्ली-**110005** द्वारा मुद्रित तथा विकासशील राज्य शोध केंद्र प्रकाशित (डीसीआरसी), एआरसी बिल्डिंग, गुरू तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-**110007** से प्रकाशन, संपादक सुनील कुमार

© डीसीआरसी2023

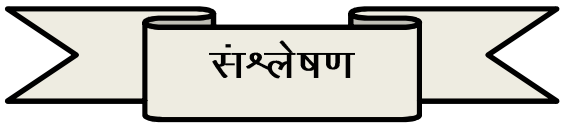

संश्लेषण

भारतीय चुनावी लोकतंत्रः परिवर्तनीयता एवं गत्यात्मकता

अनुक्रमिका

संपादकीय i-ii

1. भारतीय चुनावी लोकतंत्रः परिवर्तनीयता एवं गत्यात्मकता 1–4

– विकास यादव

– दृष्टि साह

2. पूर्वोत्तर भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनावी प्रासंगिकता 5–9

– रमेश चौधरी

3. भारतीय चुनावी लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारिता एवं योगदान 10–16

– प्रो मंजू द्विवेदी

– प्राची जायसवाल

4. मिजोरम राज्य विधानसभा चुनावः 2018 व 2023 का तुलनात्मक विश्लेषण 17–21

– सृष्टि

5. मिजोरम का परिवर्तनीय कालः अस्मिता से आधारिकता का एक अध्ययन 22–25

– अभिषेक आर्य

6. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव मे कांग्रेस की पराजय का एक अवलोकन 26–28

– नरेंद्र कुमार

6ण मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023: एक अध्ययन – हिमांशु द्विवेदी 29–32

7ण क्या बीआरएस की मौलिकता समाप्त हो रही है? – पी. अमूल्या 33–37

8ण लोकतंत्रः विकासशील इंडिया से विकसित भारतवर्ष का सफर 38–44

– डा० मनीष शर्मा

–प्रद्युमन कुमार दुबे

सम्पादकीय

निरंतरता, गुणवत्ता एवं महत्ता पर केन्द्रित सामरिक वाद–विषयों पर युवा शोधार्थियों से लेख आमंत्रण एवं प्रकाशन समसामयिक सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। प्रकाशन के इन महत्वपूर्ण सरोकारों और चुनौतियों के आलोक में वैश्विक अध्ययन केंद्र अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के 64वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा है। पाँच वर्षों से प्रकाशन की इस अकादमिक यात्रा में केंद्र एक परिवार के रुप में समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों से सामाजिक विज्ञान के प्रति अपने संकल्पित ध्येय को साकार करता आ रहा है। निरंतरता की इस कडी में संश्लेषण का यह अंश शोध के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एवं दृढ़निश्चतता को प्रदर्शित करने का ही एक सामान्य प्रयास है।

वर्ष 2023 को भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक चुनावी वर्ष के रुप में संबोधित किया जा सकता है। लोक सभा 2024 से पूर्व विभिन्न राज्य विधान सभाओं में होने वाले त्रैमासिक चुनाव एक सशक्त एवं सुदृढ़ लोकतंत्र की दृष्टि से अनेक आयाम प्रस्तुत करते हैं। हिमाचल, गुजरात एवं पूर्वोतर राज्यों के पश्चात दक्षिण भारत में मई 2023 का कर्नाटक विधान सभा चुनाव तथा नवम्बर 2023 में मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं तेलंगना के विधान सभा चुनाव विविध दृष्टिकोणों से भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति के एक परिवर्तनीय परिदृश्य को इंगित करता है।

उत्तर भारत के तीन हिन्दी–केन्द्रिक राज्यों, उत्तरपूर्व के मिजोरम तथा दक्षिण भारत के तेलांगना सहित पांच राज्यों में नवम्बर 2023 में विधान सभा चुनावों को लोक सभा 2024 के 'सेमी फाईनल' की संज्ञा के रुप में संबोधित किया जा सकता है। पांच राज्यों के इन विधान सभा चुनावों में राष्ट्रीय व राज्यीय दलों के मध्य एक प्रमुख चुनौतीपूर्ण संघर्ष देखने को मिला। पदग्राही एवं सत्ताविरोधी विरोध के मध्य पांच राज्य विधान सभा चुनावों ने एक बार पुनः स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय वाद–विषय तथा स्थानीय नीतियों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। चुनाव सर्वेक्षणों एवं निर्गम मतानिमानों ने पांचों राज्य विधान सभा चुनावों के अपेक्षित परिणामों में महिला, मजदूर और मुस्लिम मतदाताओं के रुप में 'सांइलेट वोटर्स' की भूमिका को रेखांकित किया।

राष्ट्रीय स्तर पर विषय की महत्ता तथा राज्य स्तर पर विमर्श की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने 'भारतीय चुनावी लोकतंत्रः परिवर्तनीयता एवं गत्यात्मकता' विषय पर लेख आमंत्रित किये। नौ उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य के बहुआयामी विषयों को भी संबोधित करते हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करने का एक सर्वनिष्ठ प्रयास, प्रयत्न और परिणाम है।

संपादक मंडल

शुक्रवार, 22 दिसम्बर 2023

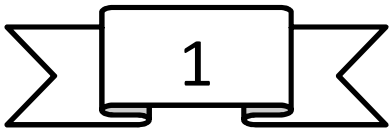

भारतीय चुनावी लोकतंत्रः परिवर्तनीयता एवं गत्यात्मकता

विकास यादव

शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

दृष्टि साह

शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

चुनावी राजनीति एवं मतदान व्यवहार समकालीन भारतीय राजनीति को सकारात्मकता के पथ पर निरन्तर लेकर जाता नजर आता है। इसी दृष्टिकोण में हाल ही के नवंबर माह में वैश्विक अध्ययन केंद द्वारा आयोजित समीक्षा श्रखंला के तहत राजस्थान राज्य के बदलते चुनावी परिदृश्य एवं राजनीति का अध्ययन किया गया। यह अध्ययन राजस्थान में हो रहे नवीन परिवर्तनो को दर्शता है। जिसमें की विभिन्न शोधार्थियों ने भाग लिया। राजस्थान की राजनीति को यदि देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जनता हर पांच वर्षों मै रिवाज बदलती है। अर्थात राजस्थान की राजनीति में अगर देखा जाए तो प्रमुखतः तो दलों का वर्चस्व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रहा है।

जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सम्मलित है। हर पांच वर्षों में सत्ता के लिए इन दो प्रमुख दलो के मध्य एक चुनावी लड़ाई प्रदर्शित होती है, जिमसें की मतदाता केंद्र बिंदु रहता है। राजस्थान में इस बार फिर से रिवाज बरकरार रहा और भारतीय जनता पार्टी ने 2023 विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता मै वापसी की। वही दूसरी और अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा और वह मात्र 69 सीटों पर रहकर सिमट गई, और वही भारतीय जनता पार्टी ने 115 सेटों पर बहुमत का आंकड़ा छुआ।

कांग्रेस ने इस चुनाव में रिवाज बदलने पर अधिक बल दिया और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी यह दावा निरंतर पार्टी करती रही, यद्यपि यह वास्तविक परिणामों में परिवर्तित नही हुआ। कांग्रेस द्वारा विभिन्न लोकलुभावन नीतियों द्वारा मतदातओं को अपनी और आकर्षित करने का प्रयास किया गया । कांग्रेस ने चिरंजीवी जैसी अनेकों नीतियों को चुनावी पटल पर रखा परन्तु

कोई भी प्रयास कांग्रेस का साकार न हो सका और राजस्थान के मतदाताओं ने फिर से रिवाज को कायम रखा। 2023 के चुनावों में एक मुख्य भूमिका महिला मतदाताओं की भी रही। महिलाओं ने इस चुनाव मे बढ़चढ़कर मतदान किया। महिलाओं के लिए प्रमुख मुद्दे सुरक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि रहे। वही दूसरी और अगर युवाओं की बात की जाए तो यह माना जाता है कि युवा मतदाता लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्तम्भ के रूप में कार्य करता है। युवा मतदाता देश के लिए सकारात्मक परिवर्तन में निर्णायक भूमिका में रहता है जिससे कि राष्ट्र निर्माण ओर अधिक सुदृढ़ हो सके। इसी अनुरूप राजस्थान की चुनावी राजनीति में भी युवाओ ने बढ़चढ़कर भाग लिया और पिछले वर्षों के अनुरूप 2023 विधानसभा चुनावों में उनका मत प्रतिशत बढ़ा, यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। युवा मतदताओं के मुद्दों की यदि बात की जाए तो उनके लिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास इत्यादि मुद्दे प्राथमिकता पर रहे। वहीं यदि बुजुर्ग मतदाताओं की प्राथमिकताओं की बात की जाए तो उनके लिए स्वास्थ्य, पेंशन इत्यादि केंद्र बिंदु रहे।

राजस्थान के इस बार के चुनावी रण में एक रोचक माहौल जो देखने को मिला वह यह रहा कि मतदताओं ने पार्टी के बजाय व्यक्ति आधारित वोट किया गया, उनके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण रहा। इस बार के विधानसभा चुनावों में बहुत सी चुनावी सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कुछ जगहों पर तो त्रिकोणीय मुकाबले भी रहे। विधायकों की जीत एव हार में एक बात जो अत्यधिक प्रचलित रही वह बागी विधायकों की रही, उन्होंने विजय या पराजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों राजनीतिक दलों के यदि बड़े नेताओं की भूमिका की भी बात की जाए तो देखा जा सकता है कि कई बड़े से बड़े नाम एवं मंत्री विफल हुए और उनको भी पराजय का सामना करना पड़ा।

राजस्थान के विधानसभा चुनावों में एक निरंतर चलती आ रही परंपरा को यदि देखा जाए तो इस राज्य में विभिन्न जातियों, समुदायो का भी प्रबल प्रभाव रहता है। राजस्थान में प्रमुखतः देखा जाए तो यहाँ गुर्जर, राजपूत, जाट, मीणा, माली इत्यादि जातियों को देखा जा सकता है। जातियों के समीकरण को देखकर एक जो महत्वपूर्ण बात यह भी निकलकर आती है कि विभिन्न राजनीतिक दल जातियों को आधार बनाकर चुनावी टिकट का बंटवारा नजर करती आती है, जिससे यह पता चलता है चुनावी रण में विभिन्न कारक एक केंद्र बिंदु रहते है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि चाहे राज्य चुनाव हो या राष्ट्रीय चुनाव, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में चुनाव सदैव एक त्योहार की तरह होते है जिमसें मतदाता एक प्रबल इकाई के रूप में कार्य करता है। राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक परिदृश्य की संकल्पना को यदि पिरोना है तो देश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है। इसी अनुरूप राजस्थान के चुनावों का अध्ययन देखा जा सकता है जिमसें की मतदताओं ने अपना मत राज्य हित को साधकर राष्ट्रीय राजनीति में योगदान दिया, और राजस्थान के इस बार के विधानसभा चुनावों का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनावों पर कितना प्रभाव प्रकशित करता है यह देखना रोचक होगा।

संदर्भ सूची

- G. Yugank, K. Arun Kumar, C Tanya (2023). "Electoral Contests in MP, Chhattisgarh, and Rajasthan - A Tale of Three Figures", *Economic and Political Weekly*, Volume No. 58, Issue no. 48, pp. 16-19.
- Sanjay Lodha (2009). "Rajasthan: Dissatisfaction and a Poor Campaign Defeat BJP", *Economic and Political Weekly*, Volume No. 44, Issue No. 6, pp.23-26.
- Yogesh Atal (2018). "Chunav Shastra Aur Rajniti", *Pratiman*, Volume No. 6, Issue No. 11, pp.11-18.

♦♦♦♦♦

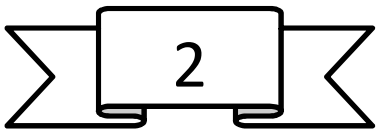

पूर्वोत्तर भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनावी प्रासंगिकता

रमेश चौधरी

शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

हाल के मिजोरम विधानसभा चुनावों में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की अपेक्षा और भी कमजोर हो गई और वह केवल 1 सीट के साथ राज्य में चौथे स्थान पर रही। 2013 में 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा के चुनावों में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 34 सीटें जीतकर राज्य में जीत हासिल की थी। हालाँकि, मिजोरम राज्य में 2018 के चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और उसकी संख्या केवल 5 सीटों पर सिमट गई। पिछले एक दशक के मिजोरम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की भांति निरंतर कम होते राजनीतिक आधार और प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है।

मिजोरम चौथा पूर्वोत्तर राज्य रहा जहां इस वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, अन्य राज्य मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड हैं, जहां कुल मिलाकर 220 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें जीत सकी। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को पिछले दशक तक पूर्वोत्तर राजनीति में एक प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी और पक्ष के रूप में माना जाता था। लेकिन इन राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन पूर्वोत्तर भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस की राजनीतिक और चुनावी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाता है।

पूर्वोत्तर भारतीय राजनीति में कांग्रेस की चुनावी प्रासंगिकता

2023 में पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन निरंतर घटते राजनीतिक आधार और चुनावी प्रासंगिकता को दर्शाता है। मिजोरम में एक विधानसभा सीट के अलावा, कांग्रेस ने मेघालय में 60 में से केवल पांच सीटें जीतीं, त्रिपुरा में 60 में से तीन सीटें जीतीं, जबकि नागालैंड में उसे कोई सीट नहीं मिली। हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई चुनावों में मतदाताओं का बड़ा वर्ग या तो क्षेत्रीय दलों या भाजपा के पक्ष में एकजुट

हुआ है। इसके परिणामस्वरूप असम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस राजनीतिक रूप से हाशिए पर चली गई है।

इन राज्यों में कांग्रेस की चुनावी गिरावट काफी हद तक पार्टी के भीतर आपसी गतिरोध और प्रभावशाली नेताओं के पार्टी से निकलने या छोड़ना मुख्य है, जिसमें हिम्मंत बिस्वा सरमा, एन. बिरेन सिंह, माणिक साहा, पेमा खांडू और मुकुल संगमा मुख्य है। पूर्वोत्तर मतदाताओं और क्षेत्रीय नेताओं की केंद्र में सत्ता में काबिज पार्टी या राज्य में उसके सहयोगी दल का समर्थन करने की सार्वजनिक प्रवृत्ति ने कांग्रेस के लिए स्थिति को और अधिक निराशाजनक बना दिया है।

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के सत्ता में आने के बाद, पहला राज्य जहां कांग्रेस नेताओं ने बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़ी वह अरुणाचल प्रदेश था, जहां 2016 में पेमा खांडू के नेतृत्व में 42 कांग्रेस विधायकों में से दो–तिहाई से अधिक भाजपा में शामिल हो गए। 2019 के अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा चुनावों में, कमजोर कांग्रेस नेतृत्व को 60 में से केवल 4 सीटें पर जीत मिली जिसका मुख्य कारण 2016 में पेमा खांडू का भाजपा में शामिल होना और कांग्रेस का एक संगठन के तौर पर कमजोर होना रहा।

2016 में, असम में पहली भाजपा सरकार बनी, जिसे बड़े पैमाने पर कई प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं ने भाजपा में शमिल हुए, जिसमें असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी थे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी का उदय मुख्य रूप से कांग्रेस की कीमत पर हुआ, जो 2011 के चुनावों में 126 में से 78 सीटों से घटकर 2016 में 26 सीटों और 2021 में 29 सीटों पर आ गई।

2017 में, मणिपुर राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन कांग्रेस नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) और नागा पीपल फ्रंट (एनपीएफ) के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन बनाकर सरकार बनाने के अपने प्रयास में विफल रही। भाजपा, जिसके पास पहले राज्य में एक भी विधायक नहीं था, बड़ी संख्या में कई कांग्रेस के विधायकों ने दल बदल किया और भाजपा में शामिल हुए जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह भी थे। जिसके बाद मणिपुर में एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी और परिणामस्वरूप 2022 के चुनाव में कांग्रेस राज्य में महज 5 सीटों पर सिमट कर रह गई।

मेघालय में भी, 2018 के चुनावों के बाद 21 विधायकों के साथ कांग्रेस मेघालय राज्य विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन एनपीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सरकार बनाई और राज्य पर शासन किया। यह कांग्रेस संगठन के प्रबंधन और क्षमता की कमी को दर्शाता है। 2021 में, पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में कांग्रेस के 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दलबदल के बाद कांग्रेस के पास मेघालय में लगभग कोई ज्ञात राजनीतिक चेहरा नहीं रह गया, 2023 के चुनावों में कांग्रेस नवोदित उम्मीदवारों पर निर्भर रही और केवल पांच सीटें जीतीं। जो कि मेघालय में कांग्रेस का सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन था।

नागालैंड में 1996 में सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस को लंबे समय से हार का सामना करना पड़ रहा है। 2002 में नागा पीपुल्स फ्रंट के उद्भव और भाजपा के क्षेत्रीय दलों के साथ उसके गठबंधन ने कांग्रेस से राज्य में उसकी अग्रणी स्थिति छीन ली। इसके बाद नेफ्यू रियो की एनडीपीपी के उदय और उसके भाजपा के साथ गठबंधन ने कांग्रेस को नागालैंड राज्य की राजनीति में हाशिए पर धकेल दिया, पिछले दो राज्य विधानसभा चुनावों में 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा में संख्या घटकर शून्य हो गई है।

त्रिपुरा में कांग्रेस हमेशा से वामपंथी दलों के समक्ष एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में राज्य की राजनीति में प्रभावशाली स्थिति में रहा, परंतु 2016 में कई कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्वीकार किया जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री मानिक साहा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेतृत्व और संगठन की कमी ने त्रिपुरा में कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता को हाशिए पर धकेल दिया है, कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में 60 सदस्य विधानसभा में मात्र तीन सीट प्राप्त हुई थी।

पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर भारत के राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनावी प्रासंगिकता और भूमिका पर प्रश्न राजनीतिक गलियारों में विवेचना का मुख्य मुद्दा रहा है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका में निरंतर गिरावट देखी गई है जिसका मुख्य कारण उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है एक बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों में प्रभावशाली नेताओं का कांग्रेस को छोड़ना जो की कांग्रेस संगठन व आलाकमान की संगठनात्मक और नेतृत्व को स्पष्ट करता है। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की चुनावी स्वीकार्यता भी है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट

यह समझ जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत में चुनावी रूप से कांग्रेस अत्यंत कमजोर और राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो रही है।

2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत कांग्रेस के लिए एक मुख्य चुनौती होगा जिसका प्रमुख कारण पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस का निरंतर गिरता जनाधार और क्षेत्रीय मुद्दों पर कमजोर है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इन कई चुनौतियों का सामना करते हुए, कांग्रेस के साथ–साथ विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई बड़ा सहयोगी नहीं है। दूसरी ओर, भाजपा के पास पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई गठबंधन सहयोगी हैं, जो पूर्वोत्तर भारत में आने वाले लोकसभा और कई विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए मुख्य चुनौती है।

संदर्भ सूची

- F. Lalramhluni (2020). "Analysis of Manifestos of Political Parties in Mizoram State Legislative Assembly Elections 2018", *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Volume no. 25, Issue No. 2, pp. 21-25.
- Padmalaya Mahapatra and Lalngaihmawia Zote (2008). "Political Development in Mizoram: Focus on the Post-Accord Scenario", *The Indian Journal of Political Science*, Volume no. 69, Issue No. 3, pp. 643–60.
- Steffi C Beingiachhiezi and Prof. J. Doungel (2023). "Free and Fair Elections: Role of Mizoram People Forum", *International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)*, Volume no. 4, Issue No. 6, pp. 242-245.

♦♦♦♦♦

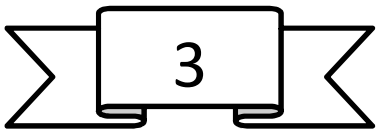

भारतीय चुनावी लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारिता एवं योगदान

प्रो मंजू द्विवेदी

पीठाधीश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ, सिद्धार्थ नगर

प्राची जायसवाल

शोधार्थी, प्रबंधन अध्ययन विभाग, सिद्धार्थ नगर

किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के डिग्री से मापा जा सकता है। — बाबा साहेब डा० अंबेडकर

भारतवर्ष एक विविधता पूर्ण और कई संस्कृतियों को समायोजित किए हुए एक अनोखा राष्ट्र है जहां प्राचीन काल से ही महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार तथा कुछ स्तरों पर पुरुषों से श्रेष्ठ भी माना गया है चाहे सामाजिक मुद्दों में भागीदारिता की बात हो या राजनीति में भागीदारिता की, उन्हें सदैव योग्यता के अनुसार उचित स्थान दिया गया है। परंतु भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद में महिलाओं को उनके जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में आजादी के पश्चात भी 75 वर्षों का समय लग गया और वर्ष 2023 में जाकर महिला आरक्षण बिल के द्वारा उन्हें केंद्र तथा राज्य विधानसभा में एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया। हेनरी क्लिंटन द्वारा कहा गया कथन इस बात की पुष्टि करता है– महिलाएं दुनिया में प्रतिभा का वो सबसे बड़ा भंडार हैं जिसका प्रयोग नहीं हुआ।

यदि हम इतिहास की बात करें तो वैदिक काल में नारी को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। अथर्ववेद में कहा गया है कि नववधू तू जिस घर में जा रही है वहां की तू साम्रगी है तेरे ससुर, सास, देवर और व्यक्ति तुझे साम्रागी समझते हुए तेरे शासन में आनंदित रहे।

नारी को शिक्षा धर्म राजनीति और संपत्ति में पुरुष के समान ही अधिकार था मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत काल में रजिया सुल्तान जो की एक स्त्री थी उन्हें उनके योग्यता के अनुसार भारत वर्ष का सुल्तान चयनित किया गया और आधुनिक भारत में भी ऐसे कई उदाहरण सम्मिलित हैं जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम सर्वोपरि लिया जा सकता है

उनके प्रशासन तकनीक की बात करें तो उनके जैसी प्रधानमंत्री वर्तमान काल में ढूंढना अत्यधिक दुष्कर है।

परंतु कुछ कुप्रथाओं तथा सामाजिक कुरीतियों ने महिलाओं के इस अधिकार तथा भागीदारिता को समय दृ समय पर घटाया भी है उदाहरण के लिए भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता जो उत्तर वैदिक काल से विकसित होनी प्रारंभ हुई जिसने महिलाओं को पुरुषों से हीन मनाना प्रारंभ कर दिया तथा जो भी आवश्यक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पद थे उन पर पुरुषों को आसीन कर दिया तथा आवश्यक निर्णयो में भी महिलाओं की भागीदारिता को कम महत्व दिया जाने लगा। इसी प्रकार सामाजिक मानदंडों, रूढ़िवादिताओं तथा शिक्षा तक पहुंच के अभाव के कारण महिलाओं की जो स्थित भारतीय समाज में व्याप्त थी वह अत्यधिक कमजोर हो गई। परंतु इसके लिए महिलाएं भी कहीं ना कहीं दोषी थी क्योंकि उनके द्वारा बिना किसी विरोध के पुरुष अधीनता स्वीकार कर ली गई।

आपकी सहमति के बिना कोई आपको हीन महसूस नहीं करवा सकता है। एलेनोर रूजवेल्ट

आजादी के बाद परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ तथा महिलाएं भारतीय राजनीति में भागीदारी के लिए अग्रसर हुई। भारतीय संविधान निर्माण में महिलाओं को भागीदारिता प्रदान की गई तथा महिला तथा पुरुष सभी को मतदान का अधिकार समान रूप से प्रदान किया गया।

भारतीय राजनीति और चुनावी तंत्र में महिलाओं की भागीदारिता और योगदान की बात करें तो समय–समय पर महिलाओं तथा महिलाओं की भागीदारिता के समर्थकों ने महिला भागीदारिता को बढ़ाने का भर्षक प्रयास किया है तथा कई बार सफलता भी प्राप्त की है जिसमें राजा राममोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू तथा एनी बेसेंट इत्यादि नाम उल्लेखनीय है इन सभी नेताओं ने महिलाओं की समाज में स्थिति को मजबूत किया तथा उन्हें राजनीति में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का अंत, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान करना, महात्मा गांधी द्वारा महिला आंदोलनकारीयो को प्रोत्साहित करना तथा सरोजिनी नायडू द्वारा नारीवादी संगठन की स्थापना करना इसका एक उत्तम उदाहरण माना जा सकता है साथ ही साथ वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वर्तमान वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण, कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी इत्यादि जैसी कई महिला नेताएं अपनी योग्यता

को सिद्ध करते हुए अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों द्वारा अन्य भारतीय महिलाओं को भी राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

आधुनिक भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रवेश

आधुनिक भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी आजादी के आंदोलन से ही आरंभ हो गई थी 20वीं शताब्दी के आंदोलन में कई महिला नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा अपना योगदान दिया। उदाहरण के लिए सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सावित्रीबाई फुले, विजयलक्ष्मी पंडित तथा कस्तूरबा गांधी आदि। आजाद भारत में 1951 में महिलाओं ने पहली बार चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया तब से लेकर आज तक भारतीय महिलाएं राजनीति में अपना स्थान बना रही हैं या यूं कहे कि बनाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तथा 2007 में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी यह दो सर्वोच्च पद प्राप्त करके महिलाओं ने भारतीय राजनीति में अपना स्थान अत्यधिक मजबूत कर लिया या यूं कहें कि एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो महिला सशक्तिकरण तथा भारतीय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राज्य स्तर पर बात करें तो उसमें भी महिलाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी अदा की है सुचेता कृपलानी, नंदिनी सत्पथी, जे जयललिता, सुश्री मायावती, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित आदि कई महिलाओं ने राज्य स्तर पर राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है सुचेता कृपलानी को केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं, संपूर्ण भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

- महिला भागीदारिता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

  - अनुच्छेद 14– कानून के समक्ष समानता, अर्थात राज्य महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव से निष्पक्ष होते हुए न्याय करेगा।
  - अनुच्छेद 15– धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अर्थात् राज्य महिलाओं को बिना लैंगिक भेदभाव के समानता का अधिकार देगा।
  - पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को प्रतिनिधित्व में आरक्षण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अपेक्षा करता है कि पंचायतों में इसके सदस्यों और अध्यक्षों दोनों के स्थानों

पर महिलाओं के लिए (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित) एक तिहाई स्थान आरक्षित किए जाएं।

इसी प्रकार ऐसे कई संवैधानिक प्रावधान है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं तथा महिलाओं की राजनीति में भागीदारिता को सुनिश्चित करते हैं।

- महिलाओं द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने वाले क्षेत्र

वर्षों से महिलाओं ने समाज के अन्याय और पूर्वाग्रह को झेला है। लेकिन आज बदलते समय के साथ उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है। उन्होंने लैंगिक रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ दिया है और अपने सपनों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये मजबूती से खड़ी हैं। उदाहरण के लिये हम कुछ महिलाओं और उनकी हाल की उपलब्धियों को देख सकते हैंरू

1. सामाजिक कार्यकर्ता

सिंधुताई सपकाल (पद्म श्री 2021– अनाथ बच्चों की परवरिश)

2. पर्यावरणविद्ः

तुलसी गौड़ा (पद्म श्री 2021– वे 'वन विश्वकोश' पुकारी जाती हैं)

3. रक्षा क्षेत्रः

अवनी चतुर्वेदी–एकल रूप से लड़ाकू विमान (मिग–21 बाइसन) का उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला

4. खेल क्षेत्र–

मैरी कॉम– ओलिंपिक में बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला।

5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन मेंः

गीता गोपीनाथ– अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री।

6. शिक्षा क्षेत्रः

- शकुंतला देवी– सबसे तेज मानव संगणना का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।
- सिविल सेवा परीक्षा 2021 में शीर्ष 3 अखिल भारतीय रैंक महिला उम्मीदवारों द्वारा हासिल की गई।

• लैंगिक समानता हेतु महिला आरक्षण विधेयक–

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के रूप में पेश 'महिला आरक्षण विधेयक, 2023' लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक–तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित करने का लक्ष्य रखता है। जो वर्तमान में राजनीति में महिलाओं की भागीदारिता बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट कदम है।

• वर्तमान भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारिता–

वर्तमान भारतीय संसद में लोकसभा में 78 और राज्य सभा में 25 महिला सांसद मौजूद हैं आजादी के पश्चात पहली बार भारतीय संसद में महिलाओं की संख्या 100 के आंकड़े को पार कर गई है तथा वर्तमान केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों में महिला मंत्रियों की उपस्थिति महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है जिसमें निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, आदि सम्मिलित है।

विश्व स्तर पर राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति –

• संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार सितंबर 2022 तक कुल 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से केवल 28 देशों में 30 महिलाएं राज्य या सरकार के निर्वाचित प्रमुख के रूप में कार्यरत थी।

• चुनाव और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में मतदाताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी में तेजी से वृद्धि और संसद में महिला प्रतिनिधित्व की धीमी वृद्धि के बीच विरोधाभास है।

• वैश्विक औसत महिला प्रतिनिधित्व में 2022 तक राष्ट्रीय सांसदों में महिला प्रतिनिधित्व का वैश्विक औसत 26.02 प्रतिशत था।

• दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति अन्य की तुलना में बदतर है उदाहरण के लिए नेपाल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 34 प्रतिशत, बांग्लादेश में 21 प्रतिशत, पाकिस्तान में 20 प्रतिशत, भूटान में 17 प्रतिशत और श्रीलंका में 5 प्रतिशत था भारत के लिए लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत से थोड़ा कम रहा है।

निष्कर्ष

अतः भारतीय चुनवी लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि दर्शाई जा रही है लेकिन अभी इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ने की आवश्यकता है पंचायतीराज, नगरपालिका और लोकसभा चुनावों में महिलाओं की आरक्षित सीटों की स्थापना ने उनकी भागीदारी में बढ़ोत्तरी किया है। हालांकि अधिकांश स्थानों पर उनका पूरे योगदान एवं भागीदारी तक पहुंचना अभी भी संभव नहीं हो पाया है क्योंकि समाज ने महिलाओं को जननी रूप में तो स्वीकार कर लिया है परंतु सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारिता की बात करें उसकी स्वीकृति अपेक्षाकृत अभी कम है समाज में सामाजिक रूप से और सार्थक रूप से बदलाव के लिए व्यापक जागरूकता, शिक्षा और समर्थन की आवश्यकता है ताकि महिलाएं सकारात्मक रूप से समाज और नैतिकता में योगदान कर सकें।

संदर्भ सूची

- Minara Yeasmin (2018). "Dr. B. R. Ambedkar's Vision for Women Empowerment", *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, Volume No. 6, Issue No. 2, pp. 1-4.
- Rajesh Kumar and Aparna Mishra (2015). "Electoral Participation of Women in India and the Role of Political Parties", *The Indian Journal of Political Science*, Volume No. 76, Issue No. 2, pp. 209-217.
- Robert Darcy and Welch Susan (1994). *Women, Elections, and Representation*, University of Nebraska Press.
- Tremblay Manon (2007) "Democracy, Representation, and Women: A Comparative Analysis", *Democratization*, Volume No. 14, Issue No. 4, pp.533- 553.

♦♦♦♦♦

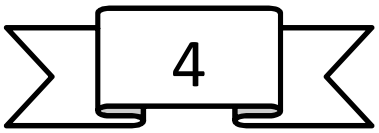

मिजोरम राज्य विधानसभा चुनावः 2018 व 2023 का तुलनात्मक विश्लेषण

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

मिजोरम राज्य क्षेत्रीय दृष्टि से भारत के उत्तरपूर्व भाग में स्थित है और पूर्व और दक्षिण में म्यांमार (बर्मा) व पश्चिम में बांग्लादेश तथा उत्तर–पश्चिम में त्रिपुरा, उत्तर में असम और उत्तर–पूर्व में मणिपुर राज्यों से घिरा हुआ है।

मिजोरम को (मिजोस की भूमि) 1954 में मिजो हिल्स जिले का नाम परिवर्तन से पहले असम के लुशाई हिल्स जिले के रूप में जाना जाता था। 1972 में यह मिजोरम के नाम से एक केंद्र प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मिजो शब्द का प्रयोग एक स्थानीय शब्द के लिए किया जात है जिसका अर्थ है पर्वतवासी अर्थात प्राकृतिक रूप से यह राज्य सौन्दर्य व सुंदरता को बटोरे हुए है। मिजो लोगों में सबसे प्रमुख हैं कुकी, पावी और लाखेर।

राजनीतिक दृष्टि से मिजोरम राज्य में नौवीं विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए है। जिसके परिणाम राज्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रथमतया, कांग्रेस या क्षेत्रीय मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) द्वारा सरकार बनाने की वर्षों पुरानी परंपरा समाप्त हो गई है। एक नई और तीसरी राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने का स्पष्ट जनादेश दिया गया है।

यदि मिजोरम राज्य में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम 2018 व 2023 का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण किया जाए, तो निम्न बिन्दु निकलकर सम्मुख प्रस्तुत होते है।

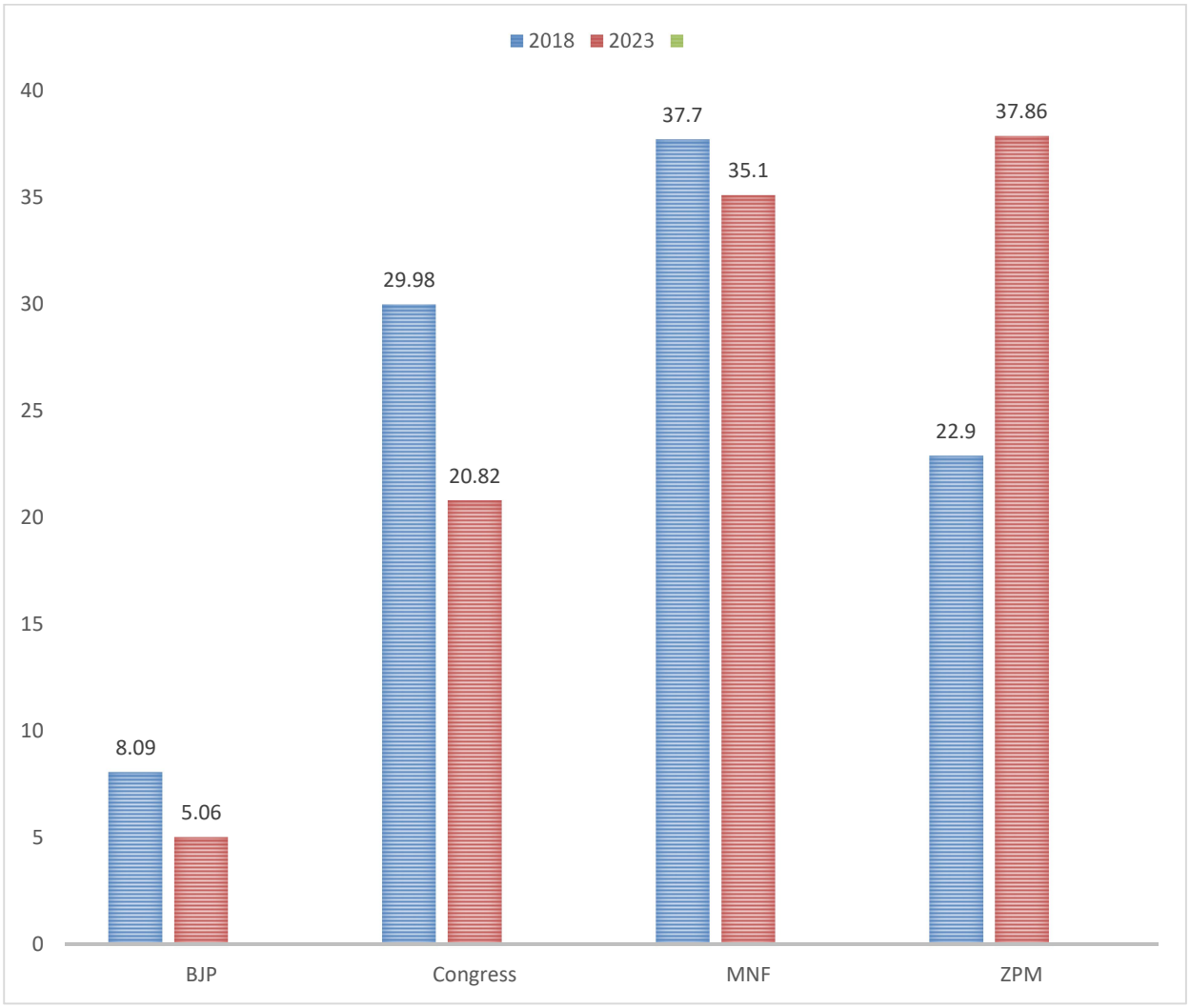

छह वर्ष पुराने जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) को मतदाताओं ने भारी जनादेश दिया है। 2018 के विधानसभा चुनावों में, तथापि ZPM एक नई पार्टी के रूप में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी किंतु यह दल मात्र छह सीटें जीत सका, जबकि MNF ने 27 सीटों के साथ विजय प्राप्त की। इन चुनावों में परिदृश्य परिवर्तित हो गया है – यह ZPM है जिसने 27 सीटें जीतीं, MNF को मात्र 10 सीटों पर छोड़ दिया। पश्चिम ग्रामीण में कांग्रेस के लिए एकमात्र सीट जीती है, काँग्रेस को यह सीट निरंतर तीसरी बार मिली है।

भले ही 40 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस की उपस्थिति पांच से घटकर एक रह गई है, भाजपा दो जीत के साथ पहली बार राज्य में अपनी संख्या बढ़ा सकती है। ऐसा तब है जब कांग्रेस के पास 20.82: और बीजेपी के पास सिर्फ 5.06: वोट थे. फिर भी, जीती गई सीटों के मामले में

भाजपा मिजोरम में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जबकि वोट शेयर के मामले में कांग्रेस तीसरे स्थान पर है।

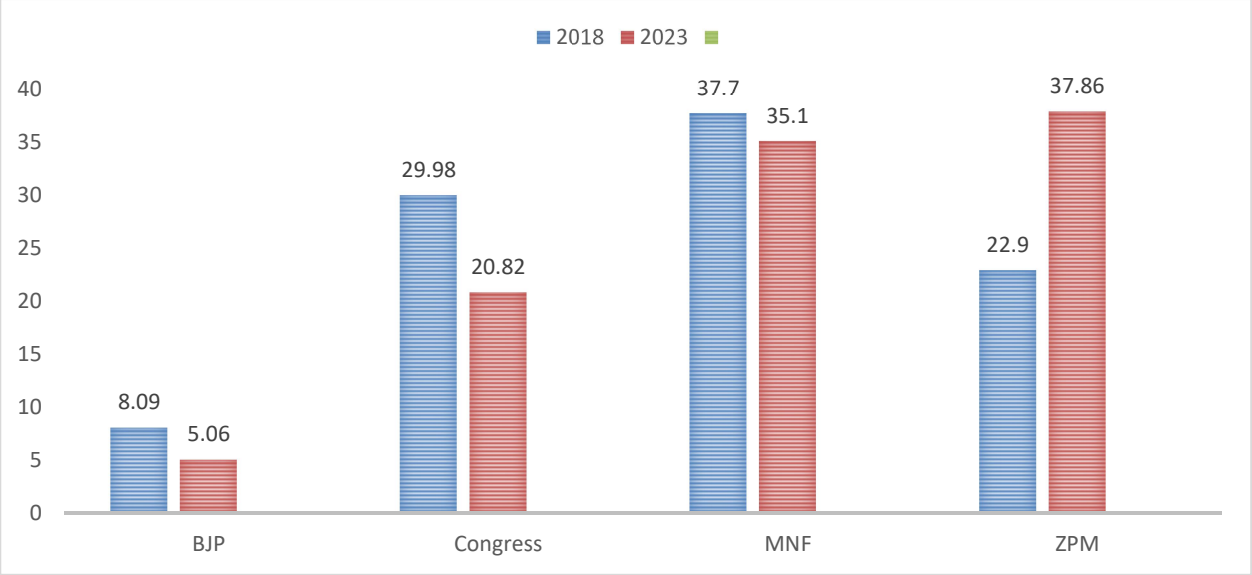

ZPM को जहां 37.7 % वोट मिले, वहीं MNF को 35.10% वोट मिले। नोटा और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ मिजोरम में भी स्वयं को आजमाने वाली आम आदमी पार्टी को कुल 1.14 फीसदी वोट मिले।

इन चुनाव परिणामों के बारे में जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि सीमावर्ती राज्य के इतिहास में पहली बार तीन महिला विधायक चुनी गईं। जबकि उनमें से दाs ZPM से संबंधित हैं (लुंगलेई पूर्व सीट से लालरिनपुई और आइजोल दक्षिण– 3 सीट से बैरिल वेनेइहसांगी), एमएनएफ के प्रोवा चकमा ने तुइपुई पश्चिम सीट जीती। जहां प्रोवा चकमा ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर चकमा समुदाय से पहली महिला विधायक बनीं।

मिजोरम राज्य में एक प्रमुख तथ्य पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है जो कि महत्वपूर्ण है राज्य में ग्रामीण व शहरी मतदाताओं के मध्य अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। ग्रामीण मतदाता एम एन एफ के साथ खड़ा दिखता है जबकि शहरी मतदाता जेड पी एम को अपनी प्राथमिकता पर रखता है। जेडपीएम ने अधिकतर शहरी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया– उसने आइजोल शहर में सभी 12 सीटें, लुंगलेई में चार और सेरछिप में सभी तीन सीटें जीतीं – एमएनएफ ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 10 सीटें जीतीं। बीजेपी ने चकमा क्षेत्र से एक सीट जीती।

कांग्रेस और भाजपा ने दक्षिण मिजोरम के सैहा और लांगतलाई जिलों में सीटें प्राप्त की । बीजेपी ने सैहा जिले की दो सीटों पर जीत प्राप्त की है और कांग्रेस ने लॉन्गटलाई जिले की दो सीटों में से एक पर जीत प्राप्त की है। बीजेपी ने मारा आदिवासी समुदाय की दोनों सीटों पर जीत प्राप्त की है।

अतः मिजोरम राज्य में सरकार को अत्यधिक सुशासन व विकास पर कार्य करने की आवश्यकता है। मिजोरम राज्य वासीयों ने परिवर्तन का चुनाव किया है। सड़क, सुरक्षा, यातायात साधन, भ्रष्टाचार, कृषि अनुउत्पादकता संबंधित समस्याओं पर कार्य करने की आवश्यकता है। आशा की जा सकती है कि विजयी दल मिजोरम राज्य के आधारिक समस्याओं पर कार्य करने में संक्षम होगा। ओर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगा।

संदर्भ सूची

- M. S. Hassan (2008). "The Breakdown in North-East India: Identity Wars or Crises of Legitimacy?", *Journal of South Asian Development*, Volume No. 3, Issue No.1, pp. 53-86.
- Padmalaya Mahapatra and Z. Lalnqaihmawia (2008). "Political Development in Mizoram: Focus on the Post-Accord Scenario", *The Indian Journal of Political Science*, Volume No. 69, Issue No. 3, pp. 643-660.
- Roluahphua (2018). "Memories and Memorials of the Mizo National Movement: Problems and Politics of Memorialization", *Economic and Political Weekly*, Volume No. 55, Issue No. 25, pp. 38-45.

♦♦♦♦♦

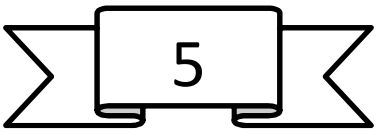

मिजोरम का परिवर्तनीय कालः अस्मिता से आधारिकता का एक अध्ययन

अभिषेक आर्य

विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

वैश्विक अध्ययन केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय समीक्षा 2023–मिजोरम विधानसभा चुनाव सर्वेक्षण के आकड़ों के माध्यम से इस आलेख में मिजोरम के परिवर्तनीय काल को दर्शाने का प्रयास किया गया है। यह आलेख लेखक के आधारिक अवलोकन पर आधारित है। इसमें मिजोरम की राज्य चुनावी राजनीति को अस्मिता से आधारिकता की परिकल्पना पर आधारित अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इस आलेख में तीन खंड हैं, पहला मिजोरम के राजनीतिक दलों के बारे में विचार–विमर्श करता है, दूसरा राज्य की राजनीति को आकार देने वाले कारकों को समझने का प्रयास करता है, जैसे चर्च, महिलाओं और युवाओं की भूमिकाय और अंतिम खंड एक नए राज्य राजनीतिक दल के उद्भव के साथ राज्य की राजनीति के परिवर्तन से संबंधित है।

मिजोरम चुनाव 2023 में चार राजनीतिक दलों की मान्यता रही है, अर्थात् भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) और जोरम पीपल्स मूवमेंट (जेडपीएम)। मिजो लोग भाजपा को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि इसमें हिंदुत्व और मोनोकल्चर की विचारधारा है और मणिपुर के मुद्दों ने भाजपा पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। ऐसे में, ऐसा लगता है कि बीजेपी तस्वीर से बाहर है, किंतु चकमा जैसे आदिवासी अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बीजेपी का कुछ आधार है, जो दिन–ब–दिन बढ़ रहा है। राजीव गांधी के पश्चात से मिजोरम में कांग्रेस की विरासत है, किंतु उसने अपनी लोकप्रियता खो दी है। हाल ही में राहुल गांधी ने मिजोरम का दौरा किया, जिसके परिणामस्वरूप मिजोस के मध्य कुछ प्रभाव पड़ा। परंतु इस तालमेल को सीटों में परिवर्तन करना कठिन है, किंतु जमीन पर कांग्रेस को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जैसा कि हम जानते हैं, एमएनएफ यहां की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है क्योंकि मिजोरम के निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका थी। हमारी टीम ने जो देखा है, सत्ता विरोधी लहर के बावजूद मिजो लोग अधिकतर सुदूर क्षेत्रों में एमएनएफ के साथ जुड़े हुए हैं और पुराने लोग आज भी उनका समर्थन करते हैं। शहरी क्षेत्र के मतदाताओं का तर्क है कि

वे दो मौजूदा पार्टियों एमएनएफ और कांग्रेस से पूर्ण रूप से परेशान हो चुके हैं। जेडपीएम नई व्यवस्था का दावा करते हुए एक विकल्प के रूप में उभरी है। ‘च्ड ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त की है, खासकर युवाओं में, किंतु सुदूर के क्षेत्रों में इसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

लेखक चर्च के प्रति लोगों के समर्पण और मिजोस के प्रति चर्च की जिम्मेदारी से आश्चर्यचकित है। एक शाम की प्रार्थना में, उनकी टीम ने एक स्थानीय चर्च का दौरा किया, जहां सभी सीटें लोगों से भरी हुई थीं और न केवल यह लोगों से भरा था, अपितु उनकी भागीदारी सराहनीय थी और चर्च ने उन्हें सख्ती से वोट डालने का आग्रह किया, किंतु स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान पर रुख अपनाया। अन्य राज्यों की तुलना में भारी मतदान के पीछे यह एक प्रमुख कारक है। कुछ भक्तों ने दावा किया कि चर्चों का भी राजनीतिक दलों के प्रति लगाव है और चुनाव से एक दिन पहले वे किसी एक अनुकूल पार्टी को वोट देने का निर्देश भी देते हैं। रविवार को सभी लोग पूरे दिन चर्च में सेवा करते हैं, वे अपने परिवार के साथ एक समारोह के अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, यही कारण है कि चुनाव आयोग को मतगणना की तारीख रविवार से सोमवार तक बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रो. जे. डौंगेल का कहना है कि महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में अधिक मुखर हैं और सरकारी अधिकारियों के रूप में उनकी संख्या भी अच्छी है, यहां तक कि मिजोरम भी एक पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन उन्हें सामने वाली राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है जो चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए चुनाव लड़ रही है। . मिजोरम की राजनीति में खासकर शहरी इलाकों में युवाओं की बड़ी भूमिका है। प्रो. लालमलस्वामा ने यंग मिजो एसोसिएशन पर प्रकाश डाला जो युवाओं को ‘च्ड के रूप में नए विकल्प की तलाश के लिए प्रभावित करता है।

मिजोरम की एक अलग राज्य की मांग के पश्चात से मिजो लोग अपनी पहचान के साथ जुड़ गए और चुनावी राजनीति उनकी पहचान पर आधारित हो गई। मिजोरम के लोग दो मौजूदा पार्टियों कांग्रेस और एमएनएफ से पूरी तरह निराश हैं, खासकर युवा। वे एक नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं जो उनके मुद्दों को पूरा कर सके क्योंकि टीम ने कई लोगों से मुलाकात की जिन्होंने तर्क दिया कि उन्हें एक नई प्रणाली की आवश्यकता है जो उनके मुद्दों का ख्याल रख सके जैसे सड़क बुनियादी ढांचा राज्य के बजट के बड़े हिस्से के बाद भी प्रमुख मुद्दों में से एक है इसके लिए अनुमति दी गई है, युवा अपनी पहचान की रक्षा ही नहीं बल्कि पूर्ण शराबबंदी के बजाय शराब के नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगस्त 2017 में एक राजनीतिक

आंदोलन से एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ जिसने पहचान से हटकर भ्रष्टाचार, सड़क और परिवहन, आधारिक संरचना, पर्यटन और विकास आदि मुद्दों पर थोड़ा बदलाव किया। इसीलिए पार्टी का नाम जोरम पीपुल्स मूवमेंट है। इसका गठन छह अलग–अलग राजनीतिक दलों और समूहों, एमपीसी, जेडएनपी, जेडईएम, जेडआरएफ, जेडडीएफ और एमपीपी के साथ किया गया है। इसने 2018 का राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा और 7 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और आइजोल नगर निगम में भी और लुंगलेई नगर परिषद चुनाव की सभी 11 सीटें जीतीं। 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव में 'च्ड का नारा है नई व्यवस्था, जो लोगों को प्रभावित कर रहा है।

निष्कर्षतः मिजोरम में चुनाव के सकारात्मक पहलू हिंसा, धांधली, भीड़ भरी रैलियां, बैनर और प्रॉक्सी वोटिंग अज्ञात हैं। मिजोरम चुनावी राजनीति में जो जातीयता–पहचान से मुद्दों की ओर परिवर्तन देख रहा है, किंतु उनकी अस्मिता को पूर्ण रूप से नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रोफेसर डौंगेल का तर्क है कि सभी राजनीतिक दलों का सामान्य राजनीतिक नारा और सामान्य दृष्टिकोण जो एकीकरण के लिए काम करना है।

संदर्भ सूची

- C Bijoy (2023). "Restructuring and Democratising Governance, Expanding Political Autonomy", *Mainstream*, Volume No. 61, Issue No. 41, pp.1-19.
- C Nunthara (1981). "Grouping of Villages in Mizoram-its Social and Economic Impact", *Economic and Political Weekly*, Volume No.16, Issue No. 30, pp. 1237-1240.
- S Barbora (2006). "Rethinking India's Counter-Insurgency in North-East", *Economic and Political Weekly*, Volume No. 41, Issue No. 35, pp. 3805-3812.

♦♦♦♦♦

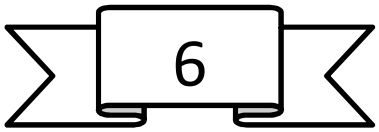

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव मे कांग्रेस की पराजय का एक अवलोकन

नरेंद्र कुमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य है। प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस है। इस राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीट हैं। चुनाव आयोग के अंतिम परिणाम में भाजपा ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस मात्र 35 सीट पर विजय प्राप्त कर पाई है। छत्तीसगढ़ मे बड़े स्तर पर आदिवासी वोट बैंक होने के कारण इसका बड़ा लाभ भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकता है। कांग्रेस की सरकार होने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ठीक छवि होने के बावजूद भी इस राज्य मे भाजपा का विजय होना कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। सबसे बड़ा संकेत यही है कि नरेंद्र मोदी पर यहां की जनता ने अपना पूरा विश्वास दिखाया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा इसका सबसे अधिक लाभ उठाने का प्रयास करेगी।

छत्तीसगढ़ के इस चुनाव मे कई महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जो इस प्रकार है। (1) कृषकों का कर्ज माफ (2) बेरोजगारी (3) युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन और शिक्षा की बेहतरी। (4) गैस, पेट्रोल और अन्य आवश्यक वस्तुओं में मुद्रास्फीति (5) कृषकों नों से बढ़ी हुई दर पर चावल खरीदने का आश्वासन। इसके अतिरिक्त और भी कई महत्वपूर्ण रहे है जिनके आधार पर मतदाता प्रभावित हुए है। जैसे (1) सरकारी कर्मचारियों को उचित भत्ता (2) समय पर नई रिक्तियां का सर्जन (3) उचित वेतन वृद्धि (4) व्यवसायियों के लिए कोई उचित नीति (5) शराब की दुकानों का उन्मूलन इत्यादि मुद्दे इस चनाव मे बहुत महत्वपूर्ण रहे। यदि मत प्राथमिकता के आधार पर देखे तो यहा की जनता ने विकास और स्वशासन को महत्वपूर्ण माना है। इसके पश्चात नेताओं के व्यक्तिगत काम के आधार पर अपना मत दिया है।

कांग्रेस की पराजय के मुख्य कारण

इस चुनाव मे कांग्रेस की पराजय के विभिन्न महत्वपूर्ण कारण रहे है। जैसे किसानों की ऋण माफी इस चुनाव मे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है किंतु कांग्रेस अपने इस वादे को मतों मे रूपान्तरण

नहीं कर पाई। जिसका मुख्य करण यह रहा कि अधिकतर कृषक इस प्रकार के वादे से प्रभावित नहीं हुए।

भारत के किसी भी राज्य में चुनाव मे जातीय समीकरण मुख्य भूमिका निभाता है। यहा पर ओबीसी मतदाता बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही वोट करता आया है। किंतु, इस बार कांग्रेस ओबीसी मतदाताओं को अपनी और सही प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाई। कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक ग्रामीण क्षेत्र था। कांग्रेस को अपने ग्रामीण मतदातों से बड़ी आशा थी किंतु बीजेपी ने ग्रामीण मतदातों को आकर्षित करने में सफल रही।

कांग्रेस सरकार के ऊपर लग रहे भष्ट्राचार के आरोप भी उसकी हार के मुख्य कारण बने। चुनाव के दौरान महादेव ऐप के के द्वारा बड़ी संख्या मे भ्रष्टाचार के आरोपो का कांग्रेस कोई विशेष तोड़ नहीं निकाल पाई। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भ्रष्टाचार के आरोपों ने कांग्रेस का नुकसान किया।

इसके मुकाबले भाजपा ने विवाहित महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 12 हजार देने और 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की ख़रीदी का वादा किया था। भाजपा ने महिलाओं को 12 हजार की रकम देने को लेकर महिलाओं से बड़ी संख्या में फॉर्म भी भरवाए, इसका भी बड़ा प्रभाव माना जा रहा है।

ऋण माफी का भूमिहीन मजदूरों और छोटे कृषकों को अधिक लाभ नहीं मिला है। राज्य मे एक वर्ग ऐसा भी जिसका मानना है कि कृषक कर्ज माफी से उन कृषकों को अधिक लाभ हुआ है जिनके पास जमीन है, छोटे और भूमिहीन कृषकों को इसका अधिक लाभ नहीं मिला।

छत्तीसगढ़ चुनाव मे मे पीएससी घोटाला, ट्राइबल फैक्टर और सत्ता विरोधी लहर और ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार का मुख्य करना रहा। बीजेपी ने महत्वपूर्ण जीत दर्ज करते हुए 54 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई। भाजपा की इस जीत का मुख्य श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जिनके चुनाव प्रचार ने भाजपा की जीत मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संदर्भ सूची

- Ajad Singh (2023). "Evaluating Human Development Trends in Chhattisgarh after Economic Reforms in India", *International Journal of Research Publication and Reviews*, Volume No. 4, Issue No.11, pp.1529-1535.
- Lakhan Choudhary (2019). **"**What Sealed BJP's Victory in Chhattisgarh?", *Economic and Political Weekly,* Volume No. 54, Issue No. 35, pp.14-17.

♦♦♦♦♦

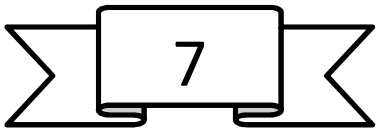

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023ः एक अध्ययन

हिमांशु द्विवेदी

विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

मध्यप्रदेश जो वर्तमान में चुनावी त्योहार को धूमधाम से मनाने में सफल रहा, उसने देश की राजनीति को एक ऐसे माहौल से अवगत करवाया कि यदि पार्टी कार्यकर्ताओं में मनोबल हो और वो इस मनोबल से मतदाताओं में विश्वास जगा सकें तो कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। इस आलेख में मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग के चुनावी व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। जो कि वैश्विक अध्ययन केंद्र के निर्देशक प्रो. सुनील कुमार चौधरी के मागदर्शन में किया गया।

प्रदेश में दो केंद्रीय राजनीतिक पार्टियां है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही मुख्य भूमिका में रहीं। तथापि बसपा भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए मैदान में प्रस्पर्धित प्रदर्शित हुई । अन्य पार्टियां और निर्दलीय विधायक भी चुनावी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण भाग बने।

मध्यप्रदेश स्वयं में इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि वहां बहुत से आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। साथ ही ग्रामीण मतदाताओं की भूमिका भी यहां विशेष हो जाती है। महिला मतदाताओं की भूमिका इस चुनाव में यहां महत्वपूर्ण नजर आई। सरकार द्वारा संचालित महिला उत्थान योजनाएं लोगों के मध्य विचार–विमर्श का स्पष्ट केंद्र रहीं। जो अधिकांश महिला मतदाताओं को प्रभावित करके अन्य मुद्दों को धूमिल करने का काम करती नजर आई।

लोगों के मध्य विकास की धीमी गति को लेकर तत्कालीन सरकार के प्रति आक्रोश था किंतु यह आक्रोश सत्ता परिवर्तन की राह पर ले जाने के लिए पर्याप्त होगा यह कहना कठिन था। मतदाता चुनावी प्रत्याशी से अधिक पार्टी के नाम या मुख्य चेहरों से अधिक सरोकार रखते नजर आए। यहां कुछ शांत मतदाता भी दिखाई पड़े। जो चुनावी राजनीति को समझने में सक्षम हैं।

आदिवासी और निर्धन समुदाय तक पार्टियों ने पहुंच बनाने का भरसक प्रयास किया है। मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर यह तबका चिंतित दिखाई पड़ता है। धार्मिक स्थलों के रूप से यह

प्रदेश संपन्न है। इसकी विशेष क्षमताएं इसे धार्मिक पर्यटन की दिशा में अग्रणी बनाने के लिए पर्याप्त हैं। किंतु यहां धर्म को राजनीति से भिन्न रखना महत्वपूर्ण हो जाता है।

कृषि पर निर्भरता यहां के लोगों को प्राथमिक उद्योगो से जोड़ने की क्षमता रखती है। किंतु यहां एक बड़ी जनसंख्या कृषि कार्यों पर लगी होने के बावजूद नवीनतम तकनीकों के आभाव से ग्रसित है, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण यहां की निर्धन है। इस अभाव में वह आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने में अक्षम हैं। जो यहां के क्रिसकों की बड़ी समस्या है। जो यहां की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। केंद्र की पीएम स्वनिधि योजना का भी लोगों के मध्य सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होता है। किसानों के बीच पैठ बनाने की सभी पार्टियों ने भरसक प्रयास किया है।

पिछले विधानसभा चुनाव का भी यहां सष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। जब कांग्रेस दल सबसे बड़े दल के रुप में सामने आकर कुछ महीनों की सरकार चलाने के बाद अंदरूनी कलह के कारण अपनी सत्ता बचाने में असफल रहा था। मतदाताओं के मध्य इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। वहीं अवसर मिलने पर भाजपा सरकार ने शिवराज सिंह चौहान (जो प्रदेश में मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं) के नेतृत्व मे विभिन्न लोक लुभावन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता के मध्य पुनः विश्वास प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते नजर आए। मामा शब्द सामाजिक स्तर पर शिवराज सिंह चौहान के महिलाओं से जुड़ाव को इंगित करता है। तथापि एक लंबे अरसे से मामा सत्ता में रहे और इसके पश्चात भी एक पंचवर्षीय और का सपना संजोना पार्टी के लिए एक अत्यधिक चुनौती पूर्ण कार्य रहा।

कांग्रेस यहां पर अपने कमलनाथ सरकार द्वारा कुछ महीनों में किए गए सकारात्मक कार्यों को पुनः भुनाने को लेकर मैदान में उतरती दिखती है। जाति आधारित जनगणना को मुख्य मुद्दों के रूप में प्रसारित करने का प्रयास यहां के मतदाताओं के बीच बेहतरीन पैठ बनाता हुआ मालूम नहीं पड़ रहा। यद्यपि कांग्रेस ने भी महिलाओं को लुभाने वाली योजनाओं को लागू करने का विश्वास मतदाताओं के मध्य रखने का प्रयास किया है। तथापि इन सभी में यह विशेष बात रही की महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में आकर राजनीतिक रूप से उनकी मत की अहमियत जानने का अवसर मिल रहा है। जिससे महिलाएं अपने चुनावी अधिकार के प्रति अधिक संवेदनशील दिखती हैं। राजनीतिक दल परिवार की भूमिका का आकलन महिलाओं को मुख्य

बिंदु पर रखकर करते नजर आ रहे हैं। जो एक सकारात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है।

किंतु साथ ही सांस्कृतिक, धार्मिक, वन्य पर्यटन का समुचित विकास, कृषि में नवीनतम तकनीकों का अभाव, निर्धनता, साक्षरता दर प्रदेश के उत्थान में बाधा दिखाई पड़ती है। जिनको दूर कर प्रदेश को तेजी से विकास पथ पर ले जाया जा सकता है। प्रदेश की भागौलिक स्थिति एवं संसाधनों का कुशलतम प्रयोग आने वाली सरकार पर निर्भर करता है जो प्रदेश को नवीनतम ऊंचाइयों मे ले जाने के सक्षम हो। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विजित भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करे तो मध्यप्रदेश देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आवश्यक योगदान कर पाएगा।

संदर्भ सूची

- Deepika Gupta (2009). "Social Bases of Politics In Madhya Pradesh", *The Indian Journal of Political Science*, Volume No. 70, Issue No.1, pp. 31–39.
- Rashmi Shrivastava (1994). "Madhya Pradesh Politics", *The Indian Journal of Political Science,* Volume No. 55, Issue No. 3, pp. 261-270.
- Yatinder Singh Sisodia (2014). "Electoral Politics in Madhya Pradesh: Explaining the BJP Consolidation", *Economic and Political Weekly*, Volume No. 2, Issue No. 2, pp. 203-214.

♦♦♦♦♦

8

क्या बीआरएस की मौलिकता समाप्त हो रही है?

पी. अमूल्या

विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

तेलंगाना राज्य हेतु तेलंगाना आंदोलन के 60 वर्षों ने तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी (टीआरएस) को जन्म दिया। कल्वाकुंतला चंद्र शेखर राव ने तेलंगाना आंदोलन का राजनीतिकरण किया था और तेलंगाना के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए टीआरएस पार्टी की स्थापना की थी, जिन पर पिछली कांग्रेस सरकार ने विचार नहीं किया था। तेलंगाना के लोगों की प्रमुख मांगें रोजगार, पानी और बिजली जैसी आधारिक आवश्यकताएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्गों का उत्थान थीं।

तेलंगाना राज्य में पहले चुनावों के बाद, टीआरएस ने 64% वोटों के साथ विजय प्राप्त की और मिशन भगीरथ, कालेश्वरम परियोजना, 24 घंटे बिजली आपूर्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से बुनियादी जरूरतों को पूरा किया, जिससे तेलंगाना के लोगों का विश्वास हासिल हुआ। सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी के प्रारंभिक दिनों में कई योजनाओं की घोषणा की और आधारिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जो लोगों को सरकार के प्रति अधिक वफादार बनाता है।

तथापि, 2019 के चुनावों में टीआरएस पार्टी ने 52% से विजय प्राप्त की, जो कि तेलंगाना में मध्यवर्ती घोटाले के कारण 12% समर्थन की गिरावट को दर्शाता है, जिसमें केटीआर के दोस्त को उत्तर देने का ठेका देने का आरोप लगा था। इस घोटाले ने टीआरएस पार्टी के शासन पर संदेह उत्पन्न कर दिया है। हुजूराबाद के उपचुनाव में बीआरएस और बीजेपी के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई, जहां बीआरएस ने समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों का वोट बैंक जीतने के लिए दलित बंधु योजना की घोषणा की। किंतु बीजेपी ने हुजूराबाद चुनाव भारी बहुमत से जीत लिया. जिस दलित बंधु की घोषणा की गई थी, उससे वोट बैंक तो हासिल हुआ किंतु अधिकांश लोगों ने इसकी आलोचना की। वारंगल के एक ऑटो चालक ने बताया कि तथापि वह बीआरएस पार्टी से संतुष्ट हैं परंतु दलित बंधु योजना से निराश हैं क्योंकि सामाजिक

रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं और इसके अतिरिक्त यह योजना केवल हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र के लिए थी जिससे अन्य वर्ग समाज निराश है। .

बीआरएस ने तेलंगाना आंदोलन की पहचान के माध्यम से प्रमुखता प्राप्त की, किंतु धीरे–धीरे यह अपनी मौलिकता खो रहा है और संकीर्ण पहचान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो उस सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं जैसे दलित बंधु, बीसी बंधु में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जिसमें जाति के आधार पर योजनाएं सम्मिलित थी।

प्रारंभ में बीआरएस तेलंगाना पहचान पर आधारित था। तेलंगाना के लोग सामान्य राज्य की पहचान के आधार पर एकजुट थे। परंतु परिवर्तन तब होता है जब टीआरएस केंद्र में सत्तारूढ़ होने का सपना देखती है और अपना नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से परिवर्तन कर भारतीय राष्ट्र समिति कर लेती है। राज्य के दर्जे को लेकर लोगों का ध्रुवीकरण धीरे–धीरे कम होता जा रहा है, जो अंततः जाति और धर्म के ध्रुवीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। तेलंगाना की एकीकृत पहचान समाप्त हो रही है और संकीर्ण पहचानें राजनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। तेलंगाना राज्य में रेड्डी और कामा प्रमुख जातियाँ मानी जाती हैं और दोनों जातियों के मध्य सत्ता संघर्ष है।

बीआरएस पार्टी में, रेड्डीयों को सत्ता में कोई हिस्सेदारी दिए बिना सिर्फ कठपुतली के रूप में प्रयोग किया गया था। इससे विशेष प्रभावशाली जाति का ध्रुवीकरण होता है और उनका झुकाव बीआरएस से कांग्रेस की ओर हो जाता है। तेलंगाना के दलित समुदाय को भी निराशा हुई क्योंकि बीआरएस प्रमुख केसीआर दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने के अपने वादे को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं. जातिगत ध्रुवीकरण उन कारकों में से एक है जो कांग्रेस को मजबूत बनाता है। बीआरएस सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं के कारण तेलंगाना में लोग जाति के आधार पर अधिक विभाजित हैं, जो सामान्य तेलंगाना पहचान को धूमिल करता है।

तेलंगाना आंदोलन को 5 जनवरी, 1969 को श्रमिकों के विरोध से गति मिली क्योंकि संयुक्त आंध्र प्रदेश में अधिकांश कामकाजी आबादी आंध्र के लोग थे। लोगों को उम्मीद थी कि अगर तेलंगाना संयुक्त आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तो तेलंगाना के लोगों के संसाधन और रोजगार फंस जायेंगे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक, तेलंगाना में बेरोजगारी दर 21.88% है जबकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार यह 23.9% है। 25

वर्ष से 33 वर्ष की आयु के बीच के 41% युवा बेरोजगार हैं। युवा लोक सेवा आयोग के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जो ठीक से आयोजित नहीं हुआ और यदि आयोजित हुआ भी तो परिणाम कोर्ट में अटक गए। बीआरएस शासनादेश में पेपर लीक का मामला छाया हुआ है। लोक सेवा आयोग के संचालन में बीआरएस की अक्षमता जिसके कारण कई छात्रों की आत्महत्या हो गई थी। तेलंगाना के गठन के बाद भी तेलंगाना के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तेलंगाना आंदोलन के कारण जन्मी बीआरएस सरकार उस मूल मुद्दे का समाधान नहीं कर पा रही है जिसके लिए उसने वादा किया था।

तेलंगाना के अधिकांश स्थानीय लोग तेलंगाना के लोगों की मुख्य मांगों को पूर्ण करने में अक्षमता के कारण सरकार के प्रति असंतोष दिखा रहे हैं। तेलंगाना आंदोलन के कारण उभरी बीआरएस पार्टी तेलंगाना के उन मूल मुद्दों की अनदेखी कर रही है जिनके लिए उसने गठन किया है। पार्टी का नाम टीआरएस से बीआरएस में परिवर्तन करना अप्रत्यक्ष रूप से तेलंगाना के लोगों को पार्टी के व्यक्तिगत हित में बदलाव के बारे में सूचित करता है जिसका 2023 के चुनावों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ बीआरएस पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति अपनी निराशा दिखाई क्योंकि पार्टी की प्रकृति निरंकुश हो गई है जहां पार्टी कार्यकर्ताओं को केसीआर के परिवार के आदेशों का पालन करना पड़ता है। तेलंगाना में रेड्डी जाति एक प्रमुख जाति थी लेकिन उनकी राजनीतिक शक्ति, विशेष रूप से बीआरएस पार्टी में निर्णय लेने की शक्ति ने उनकी शक्तियां छीन ली हैं। बीआरएस पार्टी का यह व्यवहार रेड्डी जाति को कांग्रेस के लिए एक बड़ा वोट बैंक बनाता है। वारंगल के लोगों, यदाद्री ने व्यक्त किया कि बीआरएस पार्टी की योजनाओं का लाभ केवल बीआरएस पार्टी के सदस्यों और अभिजात वर्ग द्वारा उठाया जाता है, जबकि आम लोग अभी भी अंधेरे में हैं क्योंकि वे एकीकृत आंध्र प्रदेश में थे।

तेलंगाना में एक ऑटो चालक रागय्या ने कहा कि तेलंगाना में सार्वजनिक रोजगार की कमी है और साथ ही वारंगल में निजी कंपनियां भी गायब हैं, जिसके कारण तेलंगाना में अधिकांश युवा ऑटो चालक का पेशा अपना रहे हैं, जिससे आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

निष्कर्षतः, बीआरएस सरकार इसके उद्देश्य और मूल की अनदेखी कर रही है। बीआरएस सरकार के विचलित हितों के कारण दलित बंधु, बीसी बंधु और बीसी बंधु में विभाजन जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों को जाति के आधार पर विभाजित किया जा रहा है। तेलंगाना की एक समान पहचान से लेकर जातियों की विभाजित पहचान कहीं न कहीं बीआरएस पार्टी के लिए

खतरे की स्थिति को दर्शा रही है। बेरोजगारी, पानी और राजकोष जैसे जिन मूल मुद्दों के आधार पर तेलंगाना आंदोलन ने गति पकड़ी थी, वे तेलंगाना राज्य का दर्जा मिलने के 9 साल बाद भी मुद्दे ही बने हुए हैं। ये चिंताएँ उस लुप्त होती मूल पहचान और परिसर को दर्शाती हैं जिसके आधार पर बीआरएस पार्टी का गठन हुआ था।

संदर्भ सूची

- Imtiaz Quadri (2021). "Beyond Telangana Sentiment: Reimagining Region and Culture in a New State", *Economic and Political Weekly*, Volume No. 55, Issue No. 18, pp. 51-57.
- Sreeupa Saha (2014). "The Quest for Telangana: A Charismatic Socio-Political Movement in Progress", *The Indian Journal of Political Science*, Volume No. 75, Issue No. 2, pp. 343-352.

♦♦♦♦

9

लोकतंत्रः विकासशील भारत से विकसित भारतवर्ष का सफर

डा० मनीष शर्मा
सह–आचार्य, प्रबंधन अध्ययन विभाग, सिद्धार्थ नगर
प्रद्युमन कुमार दुबे
विद्यार्थी, प्रबंधन अध्ययन विभाग, सिद्धार्थ नगर

भारत विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है और भारतवर्ष के युवाओं की इस बदलती हुई विश्व में अनेको मनोकामनाएं हैं। जब भारत का एक युवा अपनी अट्ठारह वर्ष की आयु को पूरा करता है तो भारत का संविधान उसे मतदान का अधिकार प्रदान करता है। एक युवा जब प्रथम बार मतदान करने जाता है तो उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न, कई उलझनें और सबसे अधिक एक प्रकार का हर्ष उत्पन्न होता है। यह हर्ष उस अधिकार का होता है जो उसे स्वयं अपने मनपसंद योग्य नेता का चुनाव करने का अधिकार देती है। बदलते भारत को अगर विश्व पटल पर सबसे ऊपर विराजमान होना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रोत भारत की युवा आबादी है। ऐसे में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है की लोकतंत्र के प्रति युवाओं की क्या सोच है और वे इसके प्रति कितने जागरूक हैं। युवाओं का मन जोश से ओतप्रोत और इच्छाओं से परिपूर्ण होता है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी देश के आम नागरिक के पास वह अधिकार होता है जिससे वो स्वयं यह निर्धारित करते हैं कि कौन देश को निरंतर प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है जो देश के सर्वांगीण विकास में सहयोग कर सकता है।

जब 14 अगस्त की आधी रात को भारत ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता के सूर्य रूपी प्रकाश में कदम रखा तब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, *"मध्य रात्रि की इस बेला में जब पूरी दुनिया नींद की आगोश में सो रही है, हिंदुस्तान एक नई जिंदगी और आजादी के वातावरण में अपनी आँख खोल रहा है। यह एक ऐसा पल है जो बहुत कम ही दिखता है, जब हम पुराने युग से नए युग में प्रवेश करते हैं, और जब एक युग खत्म होता है और एक देश की बहुत दिनों से दबाई गई आत्मा अचानक अपनी अभिव्यक्ति पा लेती है।"* भारत की आजादी के कुछ वर्षों बाद ही सन 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया तथा जिसके

साथ ही भारतवर्ष एक लोकतान्त्रिक, संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित हो गया। भारत देश में संविधान यद्यपि 1950 में आया हो लेकिन जब अपने राज्य की प्रजा की खुशी के लिए राजा श्री रामचन्द्र ने अपनी अर्धांगिनी सीता को वनवास जाने का आदेश दे दिया, उसी समय लोकतंत्र का उदय हो गया था।

आम नागरिकों की सहायता से धनानन्द का साम्राज्य का विनाश करके चाणक्य द्वारा एक साधारण बालक को राजगद्दी पर बिठाना यह प्रमाण था कि यह आवश्यक नहीं की इस देश में राजा का वंशज ही राजा बन सकता है बल्कि जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार तो उसे मिलना चाहिए जो उस पद के योग्य हो और जिसे देश की जनता ने चुना हो।

भारत का लोकतंत्र प्रतिनिधिक लोकतंत्र है जिसमें एक छेत्र का प्रतिनिधित्व करने वालें कुछ चुनिंदा नेताओं में से चुनाव के आधार पर जनता अपना नेता चुनती है और वह चुना हुआ नेता उस छेत्र की जनता के लिए कार्य करता है।
प्रतिनिधिक लोकतंत्र के कुछ प्रमुख बिन्दु–

• प्रतिनिधिक लोकतंत्र में देश के नागरिक उन विशेष प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो उनके लिए कानून और नीतियाँ बनाते हैं।

• इस प्रकार का लोकतंत्र अधिक आबादी वाले देशों में प्रचलित है जहां देश के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी चुनौती पूर्ण है।

• आमतौर पर प्रजातन्त्र के इस स्वरूप में चुने गए प्रतिनिधियों की एक विशिष्ट निश्चित अवधि निर्धारित होती है जिसके भीतर वह अपने मतदाताओं के हितों और आकांछाओ का प्रतिनिधित्व करते हैं।

महात्मा गांधी ने लोकतंत्र के बारे में कहा था, *"मैं लोकतंत्र को एक ऐसी चीज के रूप में समझता हूँ जो कमजोरों को भी ताकतवरों के बराबर मौका देता है।"* अगर इस कथन को सार्थक करने की बात करें तो चुनावी लोकतंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। लोकतंत्र में देश के प्रत्येक नागरिक के पास समान अधिकार होते हैं जिनसे वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपायी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा था, *"सरकारें आएंगी–जाएंगी, पार्टियां बनेंगी–बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।"* लोकतंत्र का महत्व इसीलिए है क्योंकि इसमें एक

अधिकार है, एक आजादी है जो भारत देश में रहने वाले हर नागरिक को अनेक विविधताओं के बाद भी एक दूसरे से भिन्न नहीं होने देती।

अन्य देशों की अपेक्षा भारत एक विशाल आबादी तथा अनेक विविधताओं से परिपूर्ण देश है। जब देश आजाद हुआ तब भारत के समक्ष अनेकों विविध प्रकार की समस्याएं थीं। गरीबी,भुखमरी,बेकारी,शोषण, इत्यादि समस्याएं, जिनसे किसी भी किसी अविकसित देश के लिए उससे मुक्त होना बहुत बड़ी चुनौती थी। जब भारत गणतंत्र हुआ, और देश के आम नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुआ, तब से लेकर आज तक भारतवर्ष ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। आज भारत दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह निरंतर विकासशील है। बीबीसी हिन्दी की एक लेख के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी में 83 प्रतिशत बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है जोकि चीन से मात्र 1 प्रतिशत कम है। शिक्षा के छेत्र में भारत ने विशिष्ट उन्नति प्राप्त की है। आज देश में 15 लाख से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 30 करोड़ से अधिक बच्चे शिक्षा पाते हैं। उच्च शिक्षा के छेत्र में 24 नवंबर 2023 तक भारत में कुल 1114 विश्वविद्यालय हैं जिनके लगभग 4 करोड़ से अधिक युवा शिक्षा ग्रहण कर रहें हैं। भारत ने विज्ञान और तकनीकी के छेत्र में भी आशातीत सफलता हासिल की हैं जैसे कि अंतरिक्ष अनुसंधान, चंद्रयान मिशन, मंगल मिशन इत्यादि। पहले की तुलना में आज देश की महिला शक्तियों ने भी भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया है। आज देश की 48 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है।

भारत की महिलायें आज वैश्विक स्तर पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहीं हैं और साथ ही उन सभी कार्यों में आगे आई हैं जहां कभी केवल पुरुषों का प्रभुत्व हुआ करता था। भारत की लोकसभा में महिलाओं की भागीदारिता लगभग 15 प्रतिशत है । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के द्वारा अत्यधिक विलंबता के बाद महिला आरक्षण बिल आज एक यथार्थता के रूप में प्रत्यक्ष है जिसके फलस्वरूप महिलाओं के लिए निचले और उच्च दोनों सदनों में 33 प्रतिशत स्थान संरक्षित हो जाएगा। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की थी, जिसके लिए तमाम सरकारों ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाईं। जिसके परिणामस्वरूप भारत आने वाले कुछ 3–4 वर्षों में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यूनडीपी की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पीड़ित गरीबों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। 'यूएन रिपोर्ट ऑन पावर्टी' ने भारत का जिक्र करते हुए ये बताया है कि साल 2005/2006 में जहां 55 प्रतिशत (करीब 64.45 करोड़) गरीबी रेखा

से नीचे थे, वहीं साल 2019/2021 तक ये संख्या घट गई और यह संख्या 16 प्रतिशत (23 करोड़) हो गई। इस हिसाब से अगर देखें तो पिछले 15 वर्षों में भारतवर्ष में लगभग 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आयें हैं।

लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है?

भारत एक लोकतान्त्रिक देश है पर क्या किसी देश के विकास के लिए उसका लोकतान्त्रिक होना आवश्यक है? लोकतंत्र में जहां निश्चित अवधि के लिए एक सरकार जनता के हितों का नेतृत्व करती है। लोकतंत्र में सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है जबकि उन देशों में जहां लोकतंत्र नहीं होता, वहाँ पर जनता तथा देश के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अंकुश होता है। हालांकि चीन जैसा देश जहां पर लोकतंत्र नहीं है और एक प्रकार का तानाशाही शासन है, वह विश्व पटल पर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी वहाँ पर आम नागरिक के पास आजादी नहीं है और एक प्रकार की निरंकुशता है। चीन दिन प्रतिदिन विकास तो कर रहा है पर एक आदर्श राष्ट्र बनता दिखाई नहीं देता। एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब चीन एक बड़ी आबादी के साथ और बिना लोकतंत्र के भी विश्व स्तर पर विकास कर सकता है तो आखिर भारत में लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर है कि भारतवर्ष पुरातन काल से ही हर मनुष्य के हितों के बारे में सोचने और समझने वाला राष्ट्र रहा है। लोकतंत्र के अंतर्गत जो अधिकार जनता को मिलते है उसके फलस्वरूप कोई भी उनपर तानाशाही नहीं कर सकता।

लोकतंत्र के अनेक प्रकार के गुण हैं, लाभ हैं, विशेषताएं हैं, जोकि निम्नलिखित हैंः–

•लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि देश के प्रत्येक नागरिक के पास अपना विचार व्यक्त करने, अपना मत देने और देश के विकास में भाग लेने का अधिकार है। लोकतंत्र नागरिकों के स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित होता है।

•यह एक ऐसी व्यवस्था है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक के पास समान अधिकार हो और कानून व्यवस्था को सभी के ऊपर निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए। लोकतान्त्रिक व्यवस्था का निर्माण मानवाधिकारों की बुनियाद पर होता है।

•लोकतांत्रिक व्यवस्था यह भी सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक अवस्था की परवाह किए बिना उसे स्वास्थ्य, शिक्षा, और आवाज उठाने जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। लोकतंत्र सामाजिक समानता को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है।

•लोकतंत्र में उद्यमिता और निवेश को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बनाया जाता है जिससे देश का आर्थिक विकास प्रगतिशील राहत है।

•लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सत्ता का शांतिपूर्ण और वैधानिक हस्तांतरण होता है।

निष्कर्ष :–

हर निर्णय के अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं जिसमें से आवश्यकता और वातावरण को देखते हुए किसी एक निर्णय का चुनाव किया जाता है। भारतवर्ष "एक राष्ट्र–एक चुनाव" की दिशा में अग्रसर है। इसके साथ एक प्रश्न का उदय होता है कि क्या "एक राष्ट्र–एक चुनाव" के यथार्थता में आने से भारतवर्ष का मात्र एकतरफा आर्थिक विकास होगा? नहीं, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आने से भारतवर्ष के चुनावी लोकतंत्र का कायापलट हो जाएगा। भारत देश तकनीकी के छेत्र में आगे बढ़ रहा है, और इस अवस्था में हर व्यक्ति जो अपने गाँव, अपने चुनावी छेत्र से दूर है, उसे भी मतदान का अवसर प्राप्त होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की बात करते थें, जिसमे उनका मानना था कि प्रत्येक नागरिक के पास विकास पहुंचना चाहिए। अगर विकास प्रत्येक नागरिक के पास पहुंचना चाहिए तो देश के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार भी प्रत्येक नागरिक के पास पहुँचने चाहिए। आज के समय में बहुत से ऐसे लोग भी है जो मतदान करने को एक बोझ के रूप में मानतें हैं और मतदान करने से बचते हैं। भारतवर्ष में चुनाव के प्रति आम नागरिक को यह शिक्षित और जागरूक करना आवश्यक है कि मतदान करना मात्र एक अधिकार नहीं अपितु प्रत्येक नागरिक का दायित्व भी है कि वह देश के लोकतंत्र में अपना योगदान प्रस्तुत करे जिससे कि जो भी सरकार सत्ता में आए वो जनता से किए गए अपने दावों के प्रति जवाबदेह हो। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का *"विकसित भारत विजन–2047"* का जो स्वप्न है उसमे युवाओं की भागीदारी के लिए भारत के युवाओं की आशाओं को जानने के लिए एक सर्वे किया जा रहा है। जिससे कि भारत के युवा भारतवर्ष को पुनः विश्वगुरु बनाने में अपना पूरा सहयोग दे सकें। भारत हमेशा से ही एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र

रहा है और वर्तमान में मजबूती से उस दिशा में बढ़ रहा है जहां विश्व स्तर पर लोगों की सोच को बदलने का कार्य कर रहा है। विश्व के अन्य विकसित देश भारत के प्राचीन इतिहास को तथा उसके विविधता को देखते हुए इस बात को स्वीकार करते हैं की भारत इतनी विविधताओं के बाद भी इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर आगे बढ़ रहा है। जिसे देखते हुए अफ्रीका में भी वहाँ के सभी देशों के राष्ट्रपति, गणतंत्र के प्रति अग्रसर हैं। सनातन से ओतप्रोत आर्यावर्त "वसुधैव कुटुम्बकम" की विचारधारा को मानता है। भारत का उद्देश्य मात्र भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के कल्याण का है।

संदर्भ सूची

- L Gerardo Munck (2016). "What is Democracy? A Reconceptualization of the Quality of Democracy", *Democratization,* Volume No. 23, Issue No. 1, pp. 1-26.
- Madhukar Shyam Chaturvedi and Sheila Rai (2008). "Democracy: The Gandhian Paradigm", *The Indian Journal of Political Science*, Volume No. 69, Issue No. 2, pp. 249-260.
- M Plattner and L Diamond (1970). "Why Democracy?", *Journal of Democracy*, Volume No. 1, Issue No. 1, pp. 3-5.

♦♦♦♦♦

डी सी आर सी

विकासशील राज्य शोध केंद्र

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281